भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 753
दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत का वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक गठबंधन

753. **श्री कृपानाथ मल्लाहः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की विदेश नीति बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक गठबंधन बनाने के संदर्भ में किस प्रकार विकसित हुई है; और

(ख) सरकार ने विश्व भर में भारत का प्रभाव बढ़ाने तथा रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जी-20 और 'आसियान' जैसे बहुपक्षीय मंचों का किस प्रकार लाभ उठाया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होती रहती है, जिसमें दुनिया भर में रहने और काम करने वाले भारतीयों के हित भी शामिल हैं। यह देश के बढ़ते कद और विश्व मंच पर अधिक से अधिक जिम्मेदारियां संभालने की क्षमताओं में भी परिलक्षित होता है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख फोकस इसका निकटतम और विस्तारित पड़ोस है। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध 'पड़ोस प्रथम नीति', 'एक्ट ईस्ट नीति', 'थिंक वेस्ट नीति' और 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति', और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) पहल द्वारा निर्देशित होते हैं। ये नीतियां प्रासंगिक देशों के साथ हमारे जुड़ाव को व्यापक रूप से बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड जैसी विभिन्न बहुपक्षीय पहलों में भारत की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में इसका अपना नेतृत्व भी देश के बढ़ते हितों और साझेदारी को दर्शाता है।

(ख) आसियान के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ और हमारी एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है। 2012 में आसियान-भारत संबंधों का रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन एक स्वाभाविक प्रगति थी, जो 1992 में क्षेत्रीय वार्ता साझेदार (सचिव स्तर), 1996 में वार्ता साझेदारी (मंत्री स्तर) और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी (नेताओं के स्तर) से आसियान के साथ हमारे संबंधों के उन्नयन को दर्शाती है।

आसियान +1 (भारत) रूपरेखा में भागीदारी के अलावा, आसियान क्षेत्र के साथ भारत के लिए भागीदारी के अन्य मंचों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) और विस्तारित आसियान समुद्री मंच (ईएएमएफ) शामिल हैं।

1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की जी-20 अध्यक्षता ने अपनी विकास पहलों को उजागर करने और जी-20 में वैश्विक दक्षिण के साथी देशों की विकास प्राथमिकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया। 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आम सहमति से अपनाए गए जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में भारत और वैश्विक दक्षिण देशों की विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर महत्वाकांक्षी और कार्रवाई-उन्मुख परिणामों को दर्शाया गया है, जिसमें एसडीजी, हरित विकास और पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफई) पहल पर प्रगति में तेजी लाना, त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तैनाती और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से तकनीकी परिवर्तन शामिल हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का शुभारंभ उन साझेदारियों की सीमा को दर्शाता है, जिन्हें भारत जी-20 में अपनी भागीदारी के हिस्से के रूप में बनाने में सक्षम रहा है।

******